डा. अमी याज्ञिक (गुजरात) : महोदय, मैं माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को संबद्ध करती हूं।

श्री सुजीत कुमार (ओडिशा) : महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को संबद्ध करता हूं।

DR. SASMIT PATRA (Odisha) : Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

DR. AMAR PATNAIK (Odisha) : Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRI K.C. RAMAMURTHY (Karnataka): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRIMATI VANDANA CHAVAN (Maharashtra): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, please keep the time constraint in mind. I have permitted 15 Members today, hoping that everyone will confine to two minutes, so that everybody gets an opportunity to speak here.

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री; सूचना और प्रसारण मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री प्रकाश जावडेकर) : सभापति महोदय, महेश पोद्दार जी ने जो विषय उठाया है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें रोज़ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के बारे में बहुत सुझाव और शिकायतें मिलती हैं। महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बारे में गाइडलाइन्स और डायरेक्शन्स लगभग तैयार हो गई हैं और जल्दी ही इनको लागू भी कर दिया जाएगा।

Need for Enhancement of Minimum Pension with Free medical facilities to EPS-95 Pensioners

SHRI NEERAJ DANGI (Rajasthan): Mr. Chairman, Sir, the matter that I am raising today is regarding the Employees' Pension Scheme. My demand, with your permission, is for enhancement of minimum pension and free medical facilities to the EPS-95 pensioners.

As on date, the number of pensioners, who come under this scheme, is 65 lakhs. They are sustaining merely on a meager pension of Rs. 300 to Rs. 3,000 only. This is not enough even for their food and medicines at this age. In one's old age, one cannot live without medicines. They are suffering from diabetes, blood pressure, heart ailments, asthma, TB, and now, corona also. In their old age, they cannot fight for their rights. They do not have enough money also for their treatment. During the past eleven years, from 2009 to 2020, the Government of India had appointed three Commissions. They have submitted their reports also. The Expert Committee, which submitted its report on 5th August, 2010...(*Interruptions*)..

श्री सभापति : उसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। You have mentioned about three Commissions. That's enough.

SHRI NEERAJ DANGI: These three Commissions have submitted their reports from time to time. In this pandemic period, EPS-95 pensioners have not been receiving any salary. They have been surviving merely on meagre pension. They are living in very pathetic conditions. At present, this is the burning matter in the EPFO. They are expecting a solution to their problem from the Government. I request you to enhance their minimum pension to, at least, Rs. 9,000 per month, plus DA and medical facilities.

MR. CHAIRMAN: Now, Shri Shanmugam to associate.

SHRI M. SHANMUGAM (Tamil Nadu): Sir, I associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRI TIRUCHI SIVA (Tamil Nadu): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRI P. WILSON (Tamil Nadu): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRI SUJEET KUMAR: Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

DR. AMAR PATNAIK: Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

DR. SASMIT PATRA: Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

DR. AMEE YAJNIK: Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

प्रो. मनोज कुमार झा (बिहार) : महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को संबद्ध करता हूं।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद (उत्तर प्रदेश) : महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को संबद्ध करता हूं।

श्री संजय सिंह (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली) : महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को संबद्ध करता हूं।

श्री सुशील कुमार गुप्ता (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली) : महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को संबद्ध करता हूं।

श्रीमती सीमा द्विवेदी (उत्तर प्रदेश) : महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को संबद्ध करती हूं।

DR. FAUZIA KHAN (Maharashtra): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

Direct recruitment for the post of Joint Secretary in Central Government

प्रो. राम गोपाल यादव (उत्तर प्रदेश): सभापति महोदय, भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयनित होने के बाद सेक्रेटरी और कमिश्नर स्तर पर पहुंचने के बाद सेन्ट्रल गवर्नमेंट में ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए एम्पैनलमेंट होता है। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि गवर्नमेंट सीधे ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर नियुक्तियां कर रही है। इससे तीन समस्याएं पैदा हो गई हैं। एक तो आईएएस और आईआरएस की जो पूरी फ्रैटरनिटी है, उसमें नाराज़गी है। दूसरे, लाखों की तादाद में जो बच्चे तैयारी करते हैं, उनका एक सपना होता है कि वे आईएएस बनें और देश की प्रशासनिक सेवा में जाएं। उनके मन में भी यह आक्रोश है कि हम तो पढ़ते हैं, लिखते हैं, इम्तिहान देते हैं, आईएएस कम्पीट करते हैं, तब आईएएस बनते हैं और ये सीधे बन रहे हैं। तीसरी, इससे भी ज्यादा खतरनाक स्थिति यह है कि इन appointments में रिज़र्वेशन का कोई ख्याल नहीं रखा जाता है।